कुछ राज्यों ने भी इस प्रयोजनार्थ निविदाएं आमंत्रित की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो देश भर में पहचान-पत्रों का मानक आकार तथा उनके ब्यौरे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने, पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये ब्यौरों से भिन्न कोई ब्यौरा समाविष्ट किये जाने के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) कुछ राज्य सरकार ने फोटो पहचान पत्रों के जारी किये जाने के कार्य को करवाने के लिये निविदायें आमंत्रित की हैं । तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उसने 25-4-1994 तक निविदाओं के निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया था ।

(ङ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत, कुछ नम्यता अनुज्ञात करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पहचान पत्रों में कुछ हद तक, एकरुपता बनाई रखी जाये ।

Evolution of Identity Cord by Orissa Computer Application Centre

7046. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleaded to state:

(a) whether Government propose to introduce all-purpose identity cards for the citizens;

(b) whether the Orissa Computer Application Centre has evolved a novel identity card;

(c) whether Government have *exaxaimed* the card; and

(d) if so, what decision Government have taken to adopt the same all over the counrty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ); (a) Government, in pria-ciple, agrees to the introduction of photo identity cards to all electors. No decision has, however, been taken on whether these cards can be made use of for other purposes also.

(b) The Orissa Computer Application Centre have informed that it has evolved 'Parichaya' technology which envisage creation of a National data base of basic information on citizens which can be nut to multiple applications and for giving a unique identification number to each holder of a identity card.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

7047. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानांतरित किये गये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उन्हें किन-किन स्थानों से कहां-कहां स्थानांतरित किया गया है तथा उनका स्थानांतरण किये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी;

(ग) स्थानांतरण वाले स्थानों पर कितने न्यायाधीशों ने पदभार-ग्रहण कर लिया तथा कितने न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण नहीं किया ; और